ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-4* May-2017
Innovation The Research Concept

भूटान 21 वीं सदी की रक्तहीन क्रांति का देश

श्याम नारायन पाण्डेय
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान,
इग्नू, ,नई दिल्ली

सारांश

इस लेख को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है ।प्रथम भाग में दक्षिण एशिया के देशों की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक सामरिक और स्थिति का वर्णन किया गया है तथा इसकी तुलना भारत के साथ की गयी है ।इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भूटान को चर्चा का केंद्र बनाया गया है और भारत के साथ इसके सम्बन्ध को विश्लेषित किया गया है ।द्वितीय भाग में भूटान की भौगोलिक व सामरिक स्थिति का वर्णन किया गया है तथा इसका भूटान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव है, इसका विश्लेषण किया गया है ।भूटान की अवस्थिति का उसकी विदेश–नीति पर क्या प्रभाव है और इसने किस प्रकार भूटान को अलग रहने की नीति को अपनाने में अनुकूलता प्रदान की तथा किस प्रकार चीन की नीति ने इसमें परिवर्तन के कारक की भूमिका निभाई। जबकि तृतीय भाग में भूटान के एक राजनीतिक इकाई के रुप में उदय, वहां धार्मिक शासन की स्थापना, पुनः वंशानुगत राजतन्त्र की स्थापना और अंत में संवैधानिक राजतन्त्र के रूप में इसका विकास कैसे हुआ आदि का वर्णन है ।

मुख्य शब्द : भूटान, लोकतंत्र, संवैधानिक राजतन्त्र, रक्तहीन क्रांति, जीएनएच

प्रस्तावना

दक्षिण एशिया में भारत व इसके पड़ोसी देशों की स्थिति अनेक सन्दर्भों में विशेष है, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित है वहीँ अन्य पड़ोसी देश इसके चारों तरफ फैले हुए हैं । इन सभी देशों की सीमायें (स्थलीय या समुद्री) भारत से तो मिलती हैं, परन्तु ये देश आपस में सीमा नहीं बनाते। आपस में सीमा न बनना कहीं न कहीं इन्हें द्विपक्षीय सीमा विवादों से दूर रखता है, वहीँ भारत के साथ सीमा साँझा होने के कारण इनके विवाद भारत के साथ बने हुए हैं । भारत की जनसँख्या अन्य सभी पड़ोसी देशों की जनसँख्या के योग से भी अधिक है, इसी प्रकार की स्थिति क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता को लेकर भी है । अर्थात् किसी भी क्षेत्र में ये देश संयुक्त होकर भारत की बराबरी नहीं कर सकते। इस अंतराल के कारण ये सभी दक्षिण एशियाई देश मनोवैज्ञानिक रूप से भयभीत रहते हैं तथा अकारण ही भारत को संतुलित करने हेतु सामानांतर शक्ति की तलाश में रहते हैं । अतः जब कभी भारत के साथ इनका कोई द्विपक्षीय विवाद होता है तो इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा इसमें वाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस करते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि इस क्षेत्र में महाशाक्तियों को हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त होता है, जिस कारण अनेक बार भारत को असहज होना पड़ता है ।यद्यपि दक्षिण एशिया की उपर्युक्त परिस्थितियां अनेक सन्दर्भों में भारत के लिए चुनौती उत्पन्न करती हैं, परन्तु इसके अनेक लाभ भी देखने को मिलते हैं ।

जैसा कि अब तक के भारत सरकार के सिद्धांत और व्यवहार में देखने को मिलता है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता चाहता है । क्योंकि भारत एक लोकतान्त्रिक देश है और किसी भी लोकतान्त्रिक देश में शांति–सुरक्षा और विकास इसके मूलभूत मुद्दे होते हैं । परन्तु भारत की दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने की नीति में यथोचित सफलता नहीं मिल पा रही है, इसके अनेक कारण हैं ।इनमें मुख्यतः निम्न कारण उल्लेखनीय हैं– जैसे कि दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र की अनुपस्थिति अथवा इसकी प्रारंभिक अवस्था, आतंकवाद, कट्टरता, हिंसा, सीमा–विवाद और बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप ।

उपर्युक्त परिस्थितियों के बावजूद भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश भी है जिस पर उपर्युक्त समस्याओं का प्रभाव अत्यंत न्यून है, अर्थात् इस देश में आतंकवाद, हिंसा, कट्टरता, सीमा–विवाद या तो अनुपस्थित हैं या फिर अत्यंत न्यून मात्रा में हैं ।इस परिस्थिति ने भारत के साथ संबंधों के विकास में अत्यंत सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया है ।अतः इस देश के साथ भारत का

सदाबहार सम्बन्ध रहा है, इस देश का नाम है–भूटान। अन्य देशों हेतु भारत के साथ सम्बन्ध–निर्माण में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। भारत व भूटान ने जिस प्रकार अपने संबंधों का संचालन किया है, वह उल्लेखनीय है ।भारत के द्वारा भूटान के आर्थिक व अवसंरचनात्मक विकास में सतत सहयोग किया जाता रहा है। भूटान की अलग रहने की नीति से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभार में भी पहल और सहयोग भारत द्वारा किया गया है।

शोध–प्रश्न

इस लेख के अंतर्गत यह प्रश्न उठाने की कोशिश की गयी है कि सामान्यतः सर्वाधिकारवादी शासक अपनी शक्तियों की कटौती को बर्दाश्त नहीं करता और इस हेतु जब भी मांग उठती है वह इसे निर्ममता से दबाने का प्रयास करता है और जहाँ तक संभव हो अपनी सत्ता और शक्तियों को बनाये रखने का प्रयास करता है, अरब–स्प्रिंग इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज के समय में भी सीरिया, यमन आदि देशों में इस प्रकार की हिंसा भयानक रूप में फैली हुई है, वहीँ भूटान के शासक ने वैश्वीकरण का प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप लोगों की बदलती मानसिकता का ध्यान रखकर भूटान के शासक ने सत्ता का लोकतंत्रीकरण करके अपनी सत्ता को स्थायित्व दिया। इस लेख में विश्लेष्णात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए यह बताने का प्रयास किया गया है कि भूटान में राजनीतिक परिवर्तन का क्रम क्या रहा है तथा वहां लोकतंत्र के विकास के पीछे क्या कारण उत्तरदायी रहे हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

इसके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शासक की उस मंशा व दूरदर्शिता का विश्लेषण करना है जो किसी देश की स्थिति व परिस्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। आज भूटान में जो शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, अन्यथा की स्थिति में भूटान में संभावित हिंसा का कारण बन सकता था। आज जो स्थिति नेपाल में बनी हुई है वैसी ही अराजक व हिंसा की स्थिति भविष्य में संभावित हो सकती थी। अतः उस स्थति के आने से पहले ही लिए गये लोकतान्त्रिक परिवर्तन के निर्णय ने भूटान में न सिर्फ राजवंश की स्थिति को बरकरार रखा है बल्कि लोगों की इच्छा के अनुरूप सरकारभी प्रदान किया है।

भूटान की भौगोलिक व सामाजिक स्थिति तथा उसका प्रभाव

भूटान, हिमालय के गोद में स्थित पृथ्वी के सर्वाधिक आकर्षक प्राकृतिकस्थलों में से एक है, यह पूर्वी हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अवस्थित है। भूटान आकार व जनसँख्या की दृष्टि से एक छोटा, जबकि सैन्य व आर्थिक दृष्टि से एक कमजोर देश है। यहाँ का समाज बहु–नृजातीय, बहु–भाषाभाषी, बहु–धार्मिक है। भूटान में नृजातीय आधार पर मुख्यतः चार बड़े समूह देखने को मिलते हैं– न्गालोपा, शार्कोप, खेंग और नेपाली मूल। यद्यपि 'जोन्खा' भूटान की राजकीय भाषा है, भूटान की भाषाओं में असमी, बंगाली, तिब्बती, नेपाली आदि भाषाओँ का भी प्रभाव है। उल्लेखनीय बात यह है कि भूटान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, बल्कि इसका राजकीय धर्म 'बौद्ध–धर्म' है। भूटान में बौद्ध धर्म का आगमन भारतीय गुरु पद्मसंभव के साथ हुई, जिन्होंने आठवीं शताब्दी के मध्य में भूटान की ओर प्रस्थान किया था।

कहा जाता है किसी भी देश का शासन–प्रशासन, उसकी राजनीति, आर्थिक नीति और विदेश–नीति के निर्धारण में उसकी भौगोलिक व सामाजिक स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। भूटान जो कि भौगोलिक आधार पर एक पर्वतीय व छोटे आकार का भू–आबद्ध देश है। यह दो महाशक्तियों भारत और चीन के बीच घिरा हुआ है, अतः वह भौगोलिक स्थितियों के लाभ से वंचित है। भौगोलिक स्थितियों के लाभ के अंतर्गत सागर तट को प्राथमिक महत्त्व दिया जाता है क्योंकि सागर के कारण वस्तुओं और विचारों का आदान–प्रदान सक्रिय रूप से हो सकता है। दूसरी महत्व की चीज है– विशाल भू–भाग। इस स्थिति के कारण उसके संचार, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका आदि में सीमाओं का सामना करना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सीमा तक पराश्रित राज्य के रूप में व्यवहार करना पड़ता है।

यहाँ यह महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि एक भू–आबद्ध देश जो दो ऐसी महाशक्तियों के बीच घिरा हुआ है जिनके आपसी सम्बन्ध ठीक नहीं हैं, किस देश के साथ अपने झुकाव को प्रदर्शित करेगा। भूटान ने इस उलझन का बहुत ही आसानी से हल निकाल लिया, उसने अपने संबंधों के प्रसार में भारत को चुना। भारत–भूटान की 1949 ई. की संधि इसका उदाहरण है। इसके पश्चात् से लगातार भारत–भूटान संबंधों का विकास हुआ है। भारत–भूटान संबंधों की घनिष्ठता का एक प्रमुख कारण ऐतिहासिक–सामाजिक भी है, भूटान की जनसँख्या का बड़ा भाग तिब्बती मूल का है । अतः चीन द्वारा तिब्बत के दमन ने भूटान के भारत की तरफ झुकाव को और भी बढ़ा दिया।

विदेश–नीति के सन्दर्भ में के. एम. पणिक्कर ने कहा है कि, ''चूँकि हर देश की भौगोलिक विशिष्टताओं में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए प्रत्येक देश की विदेश–नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है।" भूटान की विदेश–नीति में यह बात पूर्णतः लागू होती है। इसी प्रकार भूटान का विदेशी–व्यापार भी पूर्णतः निर्भर है और यह निर्भरता भारत पर है ।भूटान द्वारा अपने निर्यात का अधिकांश भाग भारत को निर्यात किया जाता है तथा शेष भाग भारत के द्वारा प्रदत्त मार्गों के माध्यम से अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार भूटान द्वारा किये जाने वाले आयात का अधिकांश भाग भी भारत से ही होता है और शेष भाग हेतु भारत पर निर्भरता है।

भूटान में राजनीतिक विकासक्रम

सत्रहवीं सदी के पूर्व भूटान का राजनीतिक इकाई के रूप में अस्तित्व नहीं था। 1616 ई. में 'गवांग नामग्याल' नामक एक तिब्बती लामा के नेतृत्व में भूटान का एकीकरण कर इसे एक राजनीतिक स्वरुप दिया गया। लामा द्वारा स्थापित इस शासन में धर्मराज के पद का सृजन हुआ जो शासन–प्रशासन के समस्त कार्यों को करता था। इसकी सहायता के लिए देवराज के पद का सृजन किया गया था जो धर्मराज का मंत्री होता था।

आगे चलकर देवराज का राजनीतिक क्षेत्र में एकाधिकार हो गया और धर्मराज का कार्य–क्षेत्र धार्मिक मामलों तक सीमित रह गया। आगे चलकर भूटान में अनेक देवराजों का उदय हुआ, जिस कारण वहां गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इस गृहयुद्ध के पश्चात् 1907 ई. में वांगचुक वंश के अंतर्गत वंशानुगत राजवंश की स्थापना हुई। इस राजवंश ने हाल ही में सौ वर्ष पूरे कर लिए हैं और वर्तमान में इसी राजवंश के अंतर्गत भूटान में संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित है।

इस सर्वाधिकारवादी राजतन्त्र की स्थापना के सौ वर्ष पूर्ण होने के साथ ही भूटान में संवैधानिक राजतन्त्र की स्थापना कर दी गयी और मार्च 2008 में भूटान दुनियां का नवीनतम लोकतंत्र बन गया। परन्तु यह जानने के लिए कि भूटान में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ और इसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी थे, हमें थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा।

दरअसल 1950 के दशक में तृतीय–विश्व के देशों में विऔपनिवेशीकरण और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया का आंशिक प्रभाव भूटान पर भी हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भूटान के नए शासक ने अपने राज्यारोहण के अवसर पर 1952 ई. में एक 'राष्ट्रीय–सभा' के गठन का निर्णय लिया गया। इसका नाम 'शोदगू' रखा गया। यह एक मनोनीत सभा थी जिसमें विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि राजा द्वारा मनोनीत होते थे ।यह एक परामर्शदात्री संस्था थी, जिसका कार्य राजा को सलाह देना था। इस संस्था के मनोनीत प्रकृति के होने के बावजूद इसमें नेपाली मूल की बहुसंख्या वाले दक्षिणी भूटान क्षेत्र से राष्ट्रीय–सभा में प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से भेजे जाते थे, अतः यह क्षेत्र अपवाद था। इस क्षेत्र का अपवाद होने का कारण यह था कि इस क्षेत्र में बसे हुए नेपाली नागरिक मूलतः भारतीय थे जो भूटान को पलायन कर गये थे। इन पर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान राजनीतिक और लोकतान्त्रिक अधिकारों को लेकर हुए आन्दोलन के कारण अधिक जागरूकता थी।

भूटान, जो कि अलग रहने की नीति का पालन कर रहा था, उस समय अपनी नीति में बड़ा परिवर्तन किया जब वांगचुक वंश के चतुर्थ शासक जिग्मे सिंग्ये वांगचुक सत्तासीन हुए, उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक ऐसे निर्णय लिए जो उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने भूटान के सन्दर्भ में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन का निर्णय लिया– प्रथम उन्होंने राजा की सभी शक्तियों का मनोनीत राष्ट्रीय–सभा में हस्तांतरण कर दिया और इस प्रकार राजसिंहासन की केंद्रीय शक्ति को समाप्त कर दिया। यह कदम लोकतंत्रीकरण की दिशा में पहला कदम था। द्वितीय, उन्होंने देश–दुनिया से कटे हुए भूटानी समाज को जोड़ने के लिए 1990 ई. में टेलीविजन और इन्टरनेट से भूटानी समाज को अवगत कराया। तृतीय और सबसे महत्वपूर्ण कदम उन्होंने दिसम्बर 2005 ई. में तब लिया जब उनकी आयु अभी पचास वर्ष थी, इस निर्णय के अंतर्गत उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र 'जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक' को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि भूटान को जल्द ही एक संवैधानिक राजतन्त्र में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इस प्रकार भूटान संभवतः ऐसा पहला देश होने जा रहा था जिसके सर्वाधिकार संपन्न शासक ने स्वेच्छा से अपनी शक्तियों को सीमित कर लोकतंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया था।

भूटान में लोकतंत्रः एक रक्तहीन क्रांति

वर्ष 2005 ई. में लिए गये निर्णय के आधार पर भूटान में संवैधानिक राजतन्त्र के अंतर्गत संसदीय शासन–प्रणाली को वर्ष 2008 ई. में अपना लिया गया और इसी वर्ष भूटान के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय–सभा का चुनाव संपन्न हुआ, जबकि दूसरी बार चुनाव 2013 ई. में संपन्न हुआ। इस प्रकार भूटान में लोकतंत्र सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता हुआ प्रतीत हो रहा है।

भूटान में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही यह प्रश्न सहज ही खड़ा होता है कि भूटान में लोकतंत्र की स्थापना के क्या कारण थे। आखिर जब भूटान में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीतिक मांग नहीं की जा रही थी अथवा किसी भी प्रकार का आन्दोलन नहीं चलाया जा रहा था, वहां के नागरिक अपने राजा व उसके शासन से खुश थे। फिर राजा ने अपने ही अधिकारों में कटौती कर भूटान के लोगों पर लोकतंत्र को क्यों आरोपित किया?

इसका उत्तर जानने के लिए हमें उन बातों को समझना होगा जो तत्कालीन शासक के मस्तिष्क में थीं। दरअसल ऐसा विरले ही होता है कि कोई सर्वाधिकार संपन्न शासक इतना दूरदर्शी हो जाय कि वह इतिहास की धारा को रोककर भविष्य की नीति के निर्माण का नया आधार तय करे। भूटान के चतुर्थ शासक सिंग्ये अत्यंत दूरदर्शी थे उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक ऐसे निर्णय लिए जिसके माध्यम से अंततः भूटान एक लोकतान्त्रिक देश के रूप में स्थापित हो सका। सिंग्ये इस बात को समझते थे कि वैश्वीकरण के इस युग में किसी भी देश के लिए 'अलग रहने की नीति' सफल नहीं हो सकती,अतः भूटान को इस नीति का त्याग करना होगा। वे इस बात से भी अवगत थे कि पड़ोसी देश नेपाल में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव कभी न कभी भूटान पर भी होना था। क्योंकि नेपाली मूल की बड़ी जनसँख्या भूटान में भी रहती थी, जो राजनीतिक व लोकतान्त्रिक अधिकारों को लेकर अत्यंत जागरूक थी। सिंग्ये नेपाल की उस स्थिति से बचना चाहते थे जिसके अंतर्गत वहां राजतन्त्र का समूल नाश कर दिया था। अतः उन्होंने व्यावहारिकता व सूझ–बूझ का परिचय देते हुए संवैधानिक राजतन्त्र की स्थापना का निर्णय लिया, जिससे नेपाल की स्थिति से बचकर अपने राजवंश को स्थायी रूप प्रदान किया जा सके। इस हेतु उन्होंने राजवंश की शक्तियों में कटौती कर शासन में लोकतान्त्रिक परिवर्तन करने का विकल्प चुना।

इस निर्णय के प्रकाश में हमें यह मानने में गुरेज नहीं कर सकते कि भूटान के शासक की दूरदर्शिता व समझदारी भरे इस निर्णय के कारण भूटान में लोकतान्त्रिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्रमिक व अत्यंत शांतिपूर्ण रही। अतः यदि इस परिवर्तन की तुलना इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से की जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस 'रक्तहीन क्रांति' की भांति ही भूटान में भी परिवर्तन हुए। परन्तु कुछ संदर्भो में इन दोनों में अंतर

भी देखने को मिलता है अतः यहाँ उन अंतरों का वर्णन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला अंतर तो यह है कि इंग्लैण्ड की गौरवपूर्ण क्रांति एक व्यवस्थित और अनुशासित जनांदोलन का परिणाम थी, जबकि भूटान में किसी भी प्रकार के आन्दोलन की भूमिका नहीं थी। दूसरा, इंग्लैण्ड की जनता ने राजा को गद्दी से उतार कर उसकी बेटी व दामाद को सत्तासीन किया जबकि भूटान में राजा अपने पद पर बना रहा। अंतिम, भूटान में इस राजनीतिक परिवर्तन के पीछे शासक की स्वयं की मंशा रही।

निष्कर्ष

जनसँख्या व आकार में छोटा होने तथा राजनीतिक–आर्थिक–सैन्य दृष्टि से कमजोर होने के बावजूद यह छोटा सा देश अनेक क्षेत्रों में आज दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भूटान ने न सिर्फ अपने देश में आये हुए संकट (यथा– नेपाली मूल के लोगों की समस्या) बल्कि संभावित संकट (यथा– लोकतंत्रीकरण हेतु आन्दोलन) को भी ध्यान में रखकर इनसे अहिंसात्मक ढंग से निबटने में सफलता पायी है । आज दुनियां के अधिकांश देश आतंकवाद और हिंसा की चपेट में है, वहीँ भूटान अपनी शांतिप्रिय नीति के कारण इन सभी चुनौतियों से मुक्त है। इसके साथ ही भूटानी संस्कृति की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता सदैव पर्यावरण–संकट से निबटने की प्रेरणा देती है। आज जहाँ एक तरफ दुनियां समावेशी व सतत विकास को दरकिनार कर आर्थिक विकास के पैमाना के रूप में जीडीपी को अपनाया है। भूटान ने जीएनएच को अपने विकास का पैमाना बनाकर न सिर्फ आर्थिक विकास वरन लोगों की खुशहाली के स्तर को भी इसमें शामिल किया है।

भूटान जलसंसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है, अतः जलविद्युत उत्पादन के क्षेत्र में इसकी अपार क्षमता है। इस क्षेत्र में भारत एक बड़ा सहयोगी है और भूटान की अनेक परियोजनाओं भारत ने व्यापक निवेश किया है। इसके साथ ही अनेक परियोजनाएं निर्माणाधीन व प्रस्तावित भी हैं। भूटान की अर्थव्यवस्था में वन संसाधन, कृषि, पर्यटन के अतिरिक्त जलविद्युत उर्जा का भी बड़ा योगदान है। भूटान में लोकतान्त्रिक परिवर्तन के बाद भी भारत–भूटान सम्बन्ध लगातार विकास–पथ पर अग्रसर हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने पड़ोसी देशों से सम्बन्ध विस्तार में पहले की सरकार की अपेक्षा अधिक सक्रियता दिखाई है। इसी का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली विदेश–यात्रा के लिए भूटान को चुना। इस प्रकार हम देखते हैं कि 21वीं सदी के रक्तहीन क्रांति वाले इस देश में अपार संभावनाएं हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Mishra, R.C. and Chaturvedi, M. (1996). Dakshin Asia Mein Bhutan, Pointer Publisher, Jaipur. (ISBN No. 81-7132—126-7)*
2. *Upreti, B. C. (2004). Bhutan: Dilemma of Change in a Himalayan Kingdom. Delhi: Kalinga. (ISBN No. 81-87644-65-6)*
3. *Rahul, R. (1997). Royal Bhutan: A political history. Vikas Pub. House.*
4. *Singh, N. (1972). Bhutan a Kingdom in the Himalayas: A Study of the Land, its People and their Government. New Delhi: Thomson Press (India) Limited*
5. *Ardussi, J. A., & Pommaret, F. (Eds.). (2007). Bhutan: Traditions and changes (Vol. 5). Brill. (ISBN No. 978 90 04 15555 0)*
6. *https://www.indianembassythimphu.bt/index.php*
7. *http://www.thehindu.com/thehindu/*2003/01/11/*stories/*2003011100711000*.htm*
8. *http://www.thehindu.com/opinion/columns/How-democracy-took-roots-in-Bhutan/article10752146.ece*